

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2023: एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर

Bhawana Khandelwal
(M.Ed, SET In Education)
Gangapur City, Sawai Madhopur (Rajasthan)

सार : इस शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2023 के विषय में एक व्यापक संक्षेप देना। यह प्रबंध उन अद्यतित सुधारों को परिचय कराएगा जो नई शिक्षा नीति के तहत लागू होंगे। NEP 2023 ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों की योजना बनाई है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को मॉडर्नाइज करने का लक्ष्य रखती है। यह विद्यार्थियों के उपयोगी और व्यक्तिगत विकास के लिए संपूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। इस प्रबंध में हम छम्ह 2023 के प्रमुख उद्देश्यों, मुख्य बदलावों और नीति के साथ-साथ शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में नई पहल की चर्चा करेंगे। यह प्रबंध शिक्षा के नए परिदृश्य को समझने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहल को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य है नीति के अंतर्गत शिक्षा संबंधी कर्मियों, शिक्षार्थियों, अभिभावकों और समाज के अन्य सदस्यों को NEP 2023 की महत्वपूर्ण दिशाओं के बारे में जागरूक करना है।

1. परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2023 भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस नई नीति का लक्ष्य है भारत के शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विश्वस्तरीयता के साथ समर्पित बनाना। छम्ह 2023 ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित की गई अन्य शिक्षा नीतियों की मौजूदगी को समाप्त करके एक नया और आधुनिक दौर शुरू किया है। यह नई नीति संघ, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों

और शिक्षा समुदाय के सहयोग से विकसित की गई है। [1]

NEP 2023 का मुख्य लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूर्णता की ओर ले जाना है ताकि हर एक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले और उनकी समृद्धि और सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत, शिक्षा के विभिन्न पहलों पर ध्यान दिया जाएगा जैसे कि नवाचारी शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, औद्योगिक कौशल विकास, सामाजिक न्याय और समान अवसर, शैक्षिक गवर्नेंस, विदेशी शिक्षा के प्रवेश, शिक्षार्थी समर्थन और उन्नत शिक्षा संसाधनों का विकास। [1]

यह प्रबंध NEP 2023 के महत्वपूर्ण पहलों, उद्देश्यों, स्थापना की प्रक्रिया और नीति के प्रमुख दिशानिर्देशों के बारे में विस्तृत चर्चा करेगा। इसके साथ ही, यह प्रबंध भारतीय समाज के अन्य व्यक्तियों को नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्णता और इसके संभावित प्रभावों की जागरूकता के साथ परिचित कराने का प्रयास करेगा। छम्ह 2023 एक महत्वपूर्ण चरण है जो भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय दर्जे तक पहुंचाने के लिए एक नया दौर शुरू करेगा। [1]

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई बदलाव हैं और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं: [2]

➤ स्कूल शिक्षा का सुधार

- नई शिक्षा नीति 2025 तक मौलिक साक्षरता और गणित पर केंद्रित है।
- स्कूली छात्रों को केवल कक्षा 2, 5 और 8 में परीक्षाओं में हिस्सा लेना होगा।
- 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन यह पुनर्विचार की गई है। परीक्षा साल में दो बार होगी और इसके दो भाग होंगे – एक वस्तुनिष्ठ भाग और एक वर्णनात्मक भाग। [2]
- नीति का अर्थ है कि छात्रों की पाठ्यक्रम की लघुता को कम करके उन्हें अन्य विषयों के बीच संचारी और बहुभाषी बनाने दिया जाएगा।
- 6वीं कक्षा में कोडिंग को छात्रों को परिचय कराया जाएगा और प्रायोगिक शिक्षा को अपनाया जाएगा।
- मध्याह्न भोजन योजना को सुबह की भोजन शामिल किया जाएगा। छात्रों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और सलाहकारों और सामाजिक कर्मचारियों की तैनाती के माध्यम से इसका ध्यान रखा जाएगा। [2]

➤ उच्चतर शिक्षा सुधार

- बहुविषयी ग्रामीण स्नातक कार्यक्रम में चार वर्षीय बैचलर्स डिग्री, जिसमें कई निकास विकल्प होंगे।
- 1 वर्ष के पूरा होने के बाद प्रमाणपत्र।

2 वर्ष के पूरा होने के बाद डिप्लोमा।

3 वर्ष के पूरा होने के बाद बैचलर डिग्री।

4 वर्षीय बहुविषयी बैचलर्स डिग्री (प्राथमिक विकल्प)

- अब M-Phil पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा ताकि डिग्री को समान किया जा सके।
- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी जो उच्चतर शिक्षा को नियामित करेगी।
- परिषद का लक्ष्य होगा उच्चतर शिक्षा डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की प्रगति और दर को बढ़ाना।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद उच्चतर शिक्षा को नियामित करेगी, जिसमें शिक्षक शिक्षा (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा से बाहर) शामिल होगी।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्तीय और वित्त प्रबंधन के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद बनाई जाएगी, जो मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थानांतरित करेगी।
- सामान्य शिक्षा परिषद स्नातक गुणधर्मों को तैयार करेगी। [2]
- अन्य पेनल संगठन में पशुचिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद शामिल होंगे। [2]
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसियों को अब देशभर में विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी

सौंपी जाएगी, JEE Mains और NEET के साथ साथ।

- यह नीति भारत में शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की प्रस्तावित करती है।
- विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे।
- निजी विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के शुल्क को निर्धारित किया जाएगा। [2]

3. राष्ट्रीय शिक्षा के चरण

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। जिसे निम्नलिखित रूप में कार्यान्वित किया जाएगा: [3]

- **मूल्यांकन चरण** – मूल्यांकन चरण में शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे 3 वर्ष के पूर्व स्कूल या आंगनवाड़ी के रूप में जाना जाता है, इसके बाद प्राथमिक स्कूल की कक्षा 1 और 2 के बाद आता है। यह बाल शिक्षा के 3 से 8 वर्षों को कवर करेगा, जिसमें गतिविधि-आधारित अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। [3]
- **पूर्वतैयारी चरण** – इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को धीरे-धीरे विषयों को पेश किया जाएगा, जैसे कि बोलना, पढ़ना, लिखना, शारीरिक शिक्षा, भाषा, विज्ञान और गणित।
- **मध्य चरण** – कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी में अधिक अवसरों के साथ अधिक अवस्थानिक अवधारणाओं से परिचित कराया जाएगा।
- **माध्यमिक चरण** – इस चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शामिल होंगे, जिसमें

कक्षा 9 और 10 के छात्र पहले चरण में शामिल होंगे और कक्षा 11 और 12 के छात्र दूसरे चरण में शामिल होंगे। इस चरण में छात्रों के अंदर बहुविषयक अध्ययन और गहन और विमर्शात्मक सोच को प्रबोधित करने का उद्देश्य होगा। इस चरण में छात्रों को कई विषयों के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। [3]

5+3+3+4 संरचना के माध्यम से सरकार उम्मीद करती है कि छात्रों के संज्ञानात्मक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सरकार इस प्रणाली के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के चरणों को विस्तारित करेगी ताकि उन्हें इसका लाभ मिले। 102 संरचना की तुलना में, 5+3+3+4 संरचना छात्रों की मूलभूतता से शुरू होकर सेकेंडरी चरण तक उनकी नींव को मजबूत करेगी। यह नई संरचना छात्रों को शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से बहुतायत मिलने में मदद करेगी। क्योंकि इस संरचना में 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, जबकि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए होता है। इसलिए, छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत से ही सहायता मिलेगी। [3]

इसके अलावा, इस संरचना से छात्रों की सत्यापन दरों को काफी मात्रा में सुधारा जा सकेगा। इस संरचना के प्रयोग के साथ, अधिक छात्र अपने संबंधित संस्थानों में अपनी शैक्षणिक करियर के दौरान रहेंगे। संक्षेप में कहें तो, यह नई संरचना छात्रों को हर संभव तरीके से लाभ पहुंचाएगी। इसके अलावा, इस सिस्टम के तहत अधिक व्यास्तता दर के साथ एक उच्चतर लिट्रेसी दर केवल हमारे देश के भविष्य के लिए ही लाभदायक होगी। [3]

4. नई शिक्षा नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य

नई शिक्षा नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा के मानकों को वैश्विक स्तर पर उठाना

है, जिससे देश ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में एक नेता के रूप में सामरिक हो सके। इस लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षाभीयता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। [4]

इसके लिए, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के रूप में पूर्व शिक्षा नीति के कई संशोधन किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की संभावना है। [4]

5. नई शिक्षा नीति 2023 का प्रभाव

शिक्षकों पर प्रभाव: नई शिक्षा नीति 2023 प्रभाव न केवल छात्रों पर होगा, बल्कि शिक्षकों और शैक्षणिक तकनीकों पर भी होगा। NEP 2023 के अनुसार, एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए एक बीएड डिग्री की आवश्यकता होगी। इसका ध्यानचंद आंखों में रखें कि यह बीएड कोर्स एक 4 साल की एकीकृत कोर्स होना चाहिए। इस रणनीति के कारण, स्कूलों के लिए केवल योग्य शिक्षकों की भर्ती होगी, जो निस्संदेह रूप से छात्रों के भविष्य को आकार देने में मदद करेगी। [5]

यूजी और उच्च शिक्षा के छात्रों पर प्रभाव: NEP 2023 यूजी और उच्च शिक्षा कर रहे छात्रों पर भी प्रभाव डालेगी। नीति के अनुसार, यूजी डिग्री चार वर्षों तक चलेगी और यह बहुविषयक, समग्र, और लचीली होगी। इसके अलावा, छात्रों को डिग्री कार्यक्रम से बहाल होने की कई अवसर मिलेंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक या पेशेवर क्षेत्र कोर्स के पूरा होने पर छात्रों को प्रमाणपत्र मिलेगा। दो साल के बाद उन्हें डिप्लोमा मिलेगा और तीन साल के बाद बैचलर्स डिग्री मिलेगी। [5]

पीजी कोर्स की अवधि एक से दो वर्षों तक सीमित होगी। इसके अलावा, मास्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम अब उपलब्ध नहीं होगा। कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए इस कार्यक्रम में

सबसे अधिक प्रेरणादायक निर्णय कॉलेज अनुप्राणिता प्रणाली की अस्थायी बंद करने का है। इसके अलावा, कानूनी और चिकित्सा के अलावा सभी उच्च शिक्षा के कोर्सों की पर्यावरण स्थानांतरण प्रणाली के नियामक नए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। [6]

मातृभाषा में पढ़ाने के लिए: NEP में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है कि छात्र पांचवीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा, प्रशासन ने कहा है कि यह सीमा आठवीं कक्षा तक भी बढ़ाई जा सकती है। छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ने की वजह से उन्हें प्रोफेसरों द्वारा सिखाया जाने वाला विषय समझने में बेहतरीन मदद मिलेगी। यह नीति छात्रों को अपनी मातृभाषा के बारे में और भी अधिक सीखने में मदद करेगी।

इसके अलावा, इस संरचना का उपयोग करने से छात्रों के अध्ययन में अधिक बने रहने की संभावना में भी वृद्धि होगी। इस नई संरचना के लागू होते ही अधिक छात्र अपने शैक्षणिक करियर के दौरान अपने संबंधित संस्थानों में रहेंगे। संक्षेप में, यह नई संरचना हर संभावित तरीके से छात्रों को लाभ पहुंचाएगी। इसके अलावा, इस सिस्टम के तहत बढ़ी हुई साक्षरता दर केवल हमारे देश के भविष्य के लिए ही लाभदायक होगी। [6]

6. निष्कर्ष

इस शोध प्रबंध का समापन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2023 के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक संक्षेप में ध्यान केंद्रित करता है। NEP 2023 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य समानता, गुणवत्ता, उपयोगिता और अनुकूलता को सुनिश्चित करना है।

NEP 2023 के मुख्य विशेषताओं में 5+3+3+4 संरचना, विज्ञान और गणित के महत्वाकांक्षी अध्ययन, भाषा के महत्व पर ध्यान, और

अध्यापकों के विकास का प्रमुख रूप से उच्चारण किया गया है। NEP 2023 एक ऐसी नीति है जो छात्रों को व्यापक और समर्पित शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत विकास को समृद्ध कर सकें।

इस NEP 2023 के माध्यम से, भारतीय शिक्षा प्रणाली नए मानकों, तकनीकों, और अवसरों के साथ गतिशीलता और उन्नति की ओर बढ़ रही है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में नए सोच और योजनाओं का संचालन करने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के नवीनीकरण और सामरिकता की पहल को प्रोत्साहित करेगा। छम्ह 2023 द्वारा नवीनतम शिक्षण और संशोधित विद्यार्थी-मित्रता के माध्यम से, हम एक उच्च गुणवत्ता वाली, समान्तर और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली की ओर प्रगति करेंगे।

सन्दर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023/education-gov-In, (2023, फरवरी 28)
2. एनर्जीपोर्ट, (2023, जून 24), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2023 के लाभ, विशेषताएं और पूरी जानकारी
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति: भारत में छात्रों के लिए एनईपी वास्तव में क्या अर्थ है, (2023, जून 30)
4. शर्मा, आर, (2023, जून 30), नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023: एनईपी 5334 संरचना पीडीएफ क्या है
5. सिंह, एम, (2023, जून 22), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2023: लाभ, विशेषताएं और कार्यान्वयन
6. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023: पूर्ण गाइड, (2023, मई 31)